भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3403

दिनांक 05 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ियों का आधुनिकीकरण

3403. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से देशभर में आंगनवाड़ियों को आधुनिक बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ हुए हैं;

(ग) इस भागीदारी के माध्यम से आंगनवाड़ियों में किन सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार की निकट भविष्य में आंगनवाड़ियों के आधुनिकीकरण का विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) : तथापि, मै0 वेदांता द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के भाग के रूप में समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट 11 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में अपने संसाधनों के माध्यम से 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मै0 वेदांता के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) 21 सितम्बर, 2015 को हस्ताक्षरित किया गया है।

*****